समक्ष टेक चंद ज.

टेक चंद *-याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, *-प्रतिवादी*

1967 की सिविल रिट संख्या 599

26 अक्टूबर 1967

*उत्तरी भारत नहर और जल निकासी अधिनियम (*1873 का 7) - *एस.* 20 *एवं* 30 *-ए - प्रयोज्यता-अधीक्षक नहर अधिकारी-क्या अपने पूर्व आदेश की समीक्षा कर सकते हैं* ।

निर्धारित किया गया कि उत्तरी भारत नहर और जल निकासी अधिनियम, 1873 की धारा 20 एक ऐसे व्यक्ति के आवेदन पर विचार करती है जिसे नहर से पानी नहीं मिल रहा है और यह उस व्यक्ति के मामले पर लागू नहीं होता है जो "एक पानी से प्राप्त क्षेत्रों का पुनः आवंटन चाहता है" जैसा कि धारा 30-ए में प्रदान किया गया है। धारा 20 की आवश्यकता है, कि आवेदक तब तक जल-धारा का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा जब तक कि वह इसके माध्यम से पानी की आपूर्ति के लिए आवश्यक किसी भी जल-धारा में परिवर्तन के खर्च और पहली लागत में

अपने हिस्से का भुगतान नहीं कर देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मौजूदा जल-धारा को पहले से ही अन्य अधिकार-धारकों की कीमत पर बनाए रखा गया है और धारा 20 के तहत नए आवेदक को पहली लागत का अपना हिस्सा देना होगा। धारा 30-ए के तहत आवेदन करने वाले अधिकार-धारक के मामले में, ऐसे किसी योगदान की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह पहले ही एक जल-धारा में अपना योगदान दे चुका है। संभागीय नहर अधिकारी, उस धारा के तहत, अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या शेयरधारक के आवेदन पर उसमें निर्दिष्ट सभी या किसी भी मामले के लिए एक मसौदा योजना तैयार कर सकता है। धारा 30-बी (2) के तहत, प्रभागीय नहर अधिकारी को योजना को या तो मूल रूप में या संशोधित रूप में अनुमोदित करना आवश्यक है। उपधारा (3) के अंतर्गत अधीक्षण नहर अधिकारी को योजना के विवरण के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर मंडल नहर अधिकारी द्वारा अनुमोदित योजना को संशोधित करने का अधिकार है।

निर्धारित किया गया कि अधीक्षण नहर अधिकारी के पास समीक्षा की कोई शक्ति नहीं है। एक बार धारा 30-ए और 30-बी के आधार पर लिए गए निर्णय की पुष्टि अधीक्षण नहर

अधिकारी द्वारा कर दी गई है और मंडल नहर अधिकारी द्वारा अनुमोदित योजना को स्वीकार कर लिया गया है, तो बाद में किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा या स्वयं अधीक्षण नहर अधिकारी द्वारा इसमें गड़बड़ी नहीं की जा सकती है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 *और* 227 *के तहत रिट याचिका, जिसमें प्रार्थना की गई है कि 18 मार्च, 1967 के अधीक्षण अभियंता के विवादित आदेश को रद्द करने के लिए* सर्टिओरारी, परमादेश, या कोई अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए ।'

याचिकाकर्ता के लिए आरएल शर्मा वकील ।

उत्तरदाताओं के लिए ऐड्वकेट जनरल (एच) आनंद सरूप और जे सी वर्मा एण्ड बी एस गुप्ता वकील।

निर्णय

टेक चंद ज.-याचिकाकर्ता, टेक चंद, पुत्र हरदियाल, गांव कालूवास, तहसील भिवानी, जिला हिसार, ने अधीक्षण नहर अधिकारी, पश्चिमी यमुना नहर, पश्चिमी वृत्त, रोहतक

(अनुलग्नक-ए) के आदेश संख्या 4262/29/3-जी (रोहतक), दिनांक 18 मार्च, 1967, को रद्द करते हुए एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करने की मांग की है।

इस मामले में प्रतिवादी हरियाणा राज्य, अधीक्षक नहर अधिकारी और पड़ोसी गांव नाथूवास के अधिकार धारक गुलज़ारी हैं। याचिकाकर्ता को पहले अपनी जमीन की सिंचाई के लिए आउटलेट नंबर 174580/आर से पानी मिलता था। जोतों के चकबंदी की कार्यवाही के दौरान, याचिकाकर्ता और अन्य अधिकार धारकों ने नहर विभाग से संपर्क किया और अनुरोध किया कि उनके खातों को उस आउटलेट से पर्याप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति नहीं मिल रही है और इसलिए, उनके क्षेत्रों को आउटलेट नंबर 180188/आर को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। ये दोनों आउटलेट भिवानी डिसिरिब्यूटरी में हैं और एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर हैं। याचिकाकर्ता और अन्य अधिकार-धारक जो लेट संख्या 180188/आर से पानी चाहते थे, 50 मानक एकड़ क्षेत्र के मालिक थे। उप-विभागीय नहर अधिकारी ने मांगे गए स्थानांतरण के प्रयोजनों के लिए एक योजना तैयार की; और उनके अनुसार यह उत्तरी भारत नहर और जल निकासी अधिनियम (1873 की संख्या

आठवीं) की धारा 30-ए के तहत बनाया गया था, लेकिन प्रतिस्पर्धी उत्तरदाताओं के अनुसार, इस मामले को धारा 20 के तहत निपटाया गया था। योजना विधिवत प्रकाशित की गई थी और अंततः अगस्त, 1963 में अनुमोदित की गई। यह उल्लेख किया गया था कि 11 अप्रैल, 1963 को अधिनियम के संशोधन के मद्देनजर, 1963 के पंजाब अधिनियम संख्या XXI द्वारा, योजना तैयार करने का अधिकार प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी के स्थान पर उप-विभागीय नहर पदाधिकारी को दिया गया था। धारा 30-ए से 30-एफ का संदर्भ दिया गया था । धारा 30-बी के

तहत उप-विभागीय नहर अधिकारी ने योजना को पुष्टिकरण के लिए मंडल नहर अधिकारी को प्रस्तुत किया जो 23 दिसंबर, 1963 को किया गया था। इस योजना को मंडल नहर अधिकारी द्वारा अधीक्षण नहर अधिकारी, प्रतिवादी संख्या 2 को प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने 31 जनवरी 1964 को इसकी पुष्टि भी की।

गुलजारी, प्रतिवादी संख्या 3 ने, आउटलेट नंबर 174580/आर से 180188/आर को 50 मानक एकड़ जमीन के स्थानांतरण की योजना से असंतुष्ट होते हुए संभागीय नहर अधिकारी के समक्ष आपत्तियां दाखिल कीं, जिन्हें खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने 17 जनवरी, 1964 को प्रतिवादी नंबर 2 को अपील के रूप में एक अभ्यावेदन दिया। अपील को 18 मार्च, 1967 को अनुमति दी गई और 50 मानक एकड़ क्षेत्र को आउटलेट आरडी 180188/आर में स्थानांतरित करने की स्वीकृत नहीं दी। उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी नंबर 2 को अपील का निपटारा करने में तीन साल से अधिक का समय लग गया। याचिकाकर्ता इस आदेश से व्यथित महसूस करता है, जिस पर उसने आपत्ति जताई है। एक और शाखा भी है जिस पर ध्यान दिया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने आउटलेट नंबर 180188/आर से प्रतिवादी नंबर

3 के खेतों के माध्यम से पानी की आपूर्ति के लिए उप-विभागीय नहर अधिकारी को एक आवेदन दिया था और इसे 9 सितंबर, 1965 को उनके द्वारा अनुमोदित किया गया था। प्रतिवादी नंबर 3 ने असंतुष्ट महसूस किया और डिवीजनल नहर अधिकारी के पास अपील दायर की, जिस पर बाद में 22 मार्च, 1966 को निर्णय लिया गया, उप-डिविजनल नहर अधिकारी के आदेश को संशोधित किया गया और पानी ले जाने के लिए एक अलग लिंक जल मार्ग का सीमांकन किया गया। याचिकाकर्ता के खेत में पानी ले जाने वाला चैनल प्रतिवादी संख्या 3 की भूमि से होकर नहीं गुजरेगा। संभागीय नहर अधिकारी के आदेश की प्रति अनुलग्नक बी है। प्रतिवादी संख्या 3 संशोधन से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने आगे अपील दायर की। 12 अप्रैल, 1956 को प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष, इस दलील पर कि एक क्षेत्र के हस्तांतरण के खिलाफ 17 जनवरी, 1964 की पिछली अपील पर निर्णय नहीं लिया गया था और याचिकाकर्ता को एक लिंक जल-मार्ग देने के प्रभागीय नहर अधिकारी के निर्णय पर अवैध था। प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रभागीय नहर अधिकारी से मामले का निपटारा करने के लिए कहा, लेकिन बाद वाले ने यह कहते हुए वापस लिखा कि यह बेहतर होगा यदि प्रतिवादी संख्या 3 की 17 जनवरी 1964 की

अपील, अन्य अपील के साथ प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष लंबित अपील को उसके द्वारा एक साथ निस्तारित किया जाए। प्रभागीय नहर अधिकारी की ओर से प्रतिवादी संख्या 2 को भेजे गए इस संचार की प्रतिलिपि अनुलग्नक सी है। इसमें पहले ही 18 मार्च, 1967 हो चुका है, जिसमें पूर्व आउटलेट संख्या 174580/आर से से 180188/आर को 50 मानक एकड़ क्षेत्र के हस्तांतरण को रद्द करने की बात कही गई है। याचिकाकर्ता इस निर्णय से व्यथित महसूस करता है और कहता है कि प्रतिवादी नंबर 2 ने गुलजारी की अपील को स्वीकार कर लिया है, जिसे कई कारणों से रद्द किया जा सकता है।

मुख्य कारण यह है कि विवादित आदेश धारा 20 के तहत नहीं बल्कि अधिनियम की धारा 30-ए और 30-बी के तहत दिया गया था। ये तीन खंड निर्मित होते हैं:-

> "20. मध्यवर्ती जलमार्ग के माध्यम से पानी की आपूर्ति- जब भी किसी नहर से पानी की आपूर्ति के लिए एक प्रभागीय नहर अधिकारी को आवेदन किया जाता है, और उसे यह समीचीन लगता है कि ऐसी आपूर्ति दी जानी चाहिए, और इसे किसी मौजूदा जलमार्ग के माध्यम से पहुंचाया जाना चाहिए, वह ऐसे जलस्रोत के रखरखाव के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को कारण बताने के लिए नोटिस देगा, ऐसे नोटिस की तारीख से कम से कम चौदह दिन के भीतर उक्त आपूर्ति क्यों नहीं दी जानी चाहिए; और उस दिन जांच करने के बाद, प्रभागीय नहर अधिकारी यह निर्धारित करेगा कि क्या और किस शर्त पर उक्त आपूर्ति ऐसे जलमार्ग के माध्यम से पहुंचाई जाएगी।
>
> जब ऐसा अधिकारी यह निर्धारित करता है कि नहर के पानी की आपूर्ति उपरोक्त किसी भी जलमार्ग के माध्यम से की जा सकती है, तो उसका निर्णय अधीक्षण नहर

अधिकारी द्वारा पुष्टि या संशोधित होने पर आवेदक और उक्त जलकुंड के रखरखाव के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर बाध्यकारी होगा।

ऐसा आवेदक तब तक ऐसे जलधारा का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा जब तक कि वह इसके माध्यम से आपूर्ति किए जाने के लिए आवश्यक ऐसे जलधारा के किसी भी परिवर्तन के खर्च का भुगतान नहीं कर देता है, और ऐसे जलधारा की पहली लागत का ऐसा हिस्सा भी नहीं दे देता है जैसा कि प्रभागीय या अधीक्षण नहर अधिकारी निर्धारित कर सकते हैं।

ऐसा आवेदक, जब तक वह इसका उपयोग करता है, तब तक ऐसे जलकुंड के रखरखाव में अपने हिस्से के लिए भी उत्तरदायी होगा ।

30-ए(1). इस अधिनियम में निहित किसी भी बात के बावजूद और इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन, प्रभागीय नहर अधिकारी, अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या किसी शेयरधारक के आवेदन पर, सभी या किसी भी मामले के लिए प्रदान करने के लिए एक मसौदा

योजना तैयार कर सकता है, अर्थात्:

(ए) निर्माण, परिवर्तन, जलमार्ग का विस्तार और संरेखण या किसी मौजूदा जलमार्ग का पुनर्संरेखण।

(बी) एक जलमार्ग द्वारा दूसरे जलमार्ग को प्रदान किये जाने वाले क्षेत्रों का पुनः आबंटन;

(सी) किसी भी जलस्रोत का अस्तर;

(डी) जलधारा निकासी से मिट्टी जमा करने के लिए भूमि पर कब्ज़ा;

(ई)कोई अन्य मामला जो जलस्रोत से पानी की आपूर्ति के उचित रखरखाव और वितरण के लिए आवश्यक है।

(एफ) उप-धारा (1) के तहत तैयार की गई प्रत्येक योजना, अन्य मामलों के अलावा, उसकी अनुमानित लागत, प्रस्तावित जलमार्ग का संरेखण या मौजूदा जलमार्ग का पुनर्संरेखण, जैसा भी मामला हो, आउटलेट की साइट, विवरण निर्धारित करेगी। लाभान्वित होने वाले शेयरधारकों और इससे प्रभावित होने वाले अन्य व्यक्तियों की संख्या, और योजना द्वारा कवर किए जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्र की एक स्केच।

30-बी. 1. प्रत्येक योजना, उसकी तैयारी के बाद जितनी जल्दी हो सके, प्रकाशन के इक्कीस दिनों के भीतर उसके संबंध में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए ऐसे प्रारूप और तरीके से प्रकाशित की जाएगी जो इस संबंध में बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित की जा सकती है।

2. ऐसी आपत्तियों और सुझावों, यदि कोई हों, पर विचार करने के बाद, संभागीय नहर अधिकारी योजना को या तो मूल रूप से तैयार की गई या ऐसे संशोधित रूप में अनुमोदित करेगा जैसा वह उचित समझे।

3. अधीक्षण नहर अधिकारी धारा 30-सी के तहत योजना के विवरण के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर किसी भी समय या अनुमोदित योजना से पीड़ित किसी भी व्यक्ति के आवेदन पर स्वप्रेरणा से संभागीय नहर अधिकारी द्वारा अनुमोदित योजना को संशोधित कर सकता है:

बशर्ते कि प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा । शब्द "वॉटरकोर्स" को धारा

3 के तहत परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है "कोई भी चैनल जिसे नहर से पानी की आपूर्ति की जाती है, लेकिन जिसका रखरखाव राज्य सरकार की लागत पर नहीं किया जाता है, और ऐसे किसी भी चैनल से संबंधित सभी सहायक कार्य।"

याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि धारा 20 ऐसे व्यक्ति के आवेदन को संदर्भित करती है जो अब तक नहर से पानी प्राप्त नहीं कर रहा है और यह उस व्यक्ति के मामले पर लागू नहीं होता है जो अपने द्वारा सेवित क्षेत्रों का वास्तविक आवंटन चाहता है। एक जलस्रोत से दूसरे जलस्रोत" जैसा कि धारा 30-ए में प्रदान किया गया है, धारा 20 के लिए आवश्यक है कि आवेदक तब तक जलस्रोत का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा जब तक कि उसने पानी की आपूर्ति के लिए आवश्यक ऐसे किसी भी जलस्रोत के विकल्प के खर्च का भुगतान नहीं कर दिया हो, यह और ऐसे जलकुंड की *पहली लागत का ऐसा हिस्सा भी।* महत्वपूर्ण बात यह है कि मौजूदा जलमार्ग को पहले से ही अन्य अधिकार धारकों की कीमत पर बनाए रखा गया है और धारा 20 के तहत नए आवेदक को पहली लागत के हिस्से में योगदान करना होगा। धारा 30-ए के तहत आवेदन करने वाले अधिकार

धारक के मामले में, उसने पहले ही एक जलकुंड में अपना योगदान दे दिया है। मुझे लगता है कि याचिकाकर्ता के तर्क में कुछ दम है।

आईबी अधिसूचना संख्या 3041-आर-284/45, दिनांक 18 जनवरी, 1946 द्वारा अधिनियम की धारा 20 के तहत बनाए गए नियम 2 में प्रावधान है कि धारा 20 के तहत आने वाले मामले में, प्रभागीय नहर अधिकारी इच्छुक पार्टियों को अपने निर्णय की घोषणा करेगा।, और ऐसी घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर ऐसे निर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति अधीक्षण नहर अधिकारी के समक्ष लिखित रूप में आपत्ति दर्ज करा सकता है। इस प्रकार, अधीक्षण नहर अधिकारी को आपत्ति पर विचार करने और प्रभागीय नहर अधिकारी के निर्णय की पुष्टि या संशोधन करने की शक्ति दी जाती है। प्रतिवादी संख्या 3 के अनुसार, आक्षेपित निर्णय इसी नियम के तहत किया गया था। लेकिन यदि धारा 20 लागू नहीं है तो इस नियम का कोई फायदा नहीं है।

दूसरी ओर, धारा 30-ए यह स्पष्ट करती है कि प्रभागीय नहर अधिकारी अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या किसी शेयरधारक

के आवेदन पर उसमें निर्दिष्ट पांच मामलों में से सभी या किसी एक को प्रदान करने के लिए एक मसौदा योजना तैयार कर सकता है। मेरे विचार से, यह एक ऐसा मामला है जो (बी) के अंतर्गत आता है, एक जलमार्ग द्वारा दूसरे जलमार्ग द्वारा प्रदान किए जाने वाले क्षेत्रों का पुनः आवंटन। धारा 30-बी, उप-धारा (2) के तहत, प्रभागीय नहर अधिकारी को योजना को या तो मूल रूप में या संशोधित रूप में अनुमोदित करना आवश्यक है। यह 23 दिसंबर, 1963 को किया गया था। उप-धारा (3) के तहत, अधीक्षण नहर अधिकारी को योजना के विवरण के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर योजना को संशोधित करने की शक्ति है । संभागीय नहर अधिकारी. यह तदनुसार 31 जनवरी, 1964 को किया गया था, यह तथ्य लिखित बयान के पैरा 5 में भी स्वीकार किया गया है। 31 जनवरी 1964 का यह आदेश नहीं हो सका।

बाद में समीक्षा की गई क्योंकि अधीक्षण नहर अधिकारी के पास समीक्षा की ऐसी कोई शक्ति नहीं है। मेरा ध्यान दीप *चंद और अन्य* बनाम *अतिरिक्त निदेशक, कॉन्सॉलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स और अन्य (1)* मामले में पूर्ण पीठ के फैसले की ओर आकर्षित

किया गया है, जिसमें कहा गया था कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 में आरक्षित अंतर्निहित शक्तियों का सहारा नहीं लिया जा सकता है। न्यायिक या अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण को उसके द्वारा पारित किसी भी आदेश को इस आधार पर बदलने या बदलने की अनुमति देने के लिए कि बाद में इसे गुण-दोष के आधार पर गलत माना गया। इसके अलावा, तीन साल से भी अधिक समय बाद 18 मार्च, 1987 को लिया गया अधीक्षण नहर अधिकारी का निर्णय, हालांकि इसका 31 जनवरी, 1964 के उनके पहले के निर्णय को उलटने का प्रभाव था, लेकिन इसे किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं माना जा सकता है। अधिनियम के तहत. उनका 31 जनवरी, 1964 का पिछला निर्णय निर्णायक हो गया था। एक बार जब धारा 30-ए और 30-बी के आधार पर निर्णय की पुष्टि अधीक्षण नहर अधिकारी द्वारा कर दी जाती है और मंडल नहर अधिकारी द्वारा अनुमोदित योजना को स्वीकार कर लिया जाता है, तो बाद में अधीक्षण नहर अधिकारी द्वारा भी इसमें गड़बड़ी नहीं की जा सकती है। या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा. याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए किसी अन्य बिंदु का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।

मुझे लगता है कि मामले के इन तथ्यों पर, धारा 30-ए (1)

(बी) के प्रावधान आकर्षित होते हैं, न कि धारा 20 के। 18 मार्च, 1967 को अधीक्षण नहर अधिकारी द्वारा पारित आदेश (अनुलग्नक ए) , क्षेत्राधिकार के बिना और शून्य था। अत: याचिका स्वीकार की जाती है। इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता विवादित आदेश को रद्द करने के लिए *उत्प्रेषण रिट जारी करने का हकदार है।* मैं तदनुसार ऑर्डर करता हूं। इन परिस्थितियों में, मैं पार्टियों को अपनी लागत स्वयं वहन करने का आदेश देता हूँ।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रीतिका शर्मा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
करनाल, हरियाणा